श्री अर्जुन सिंह: सभापति जी, सर्व शिक्षा जैसाकि इसका नाम है, यह देश के सभी बच्चों के लिए है और इसमें माइनोरिटी के बच्चे भी शामिल हैं। वे अलग हैं, ऐसी बात नहीं है। जहां तक किसी विशेष अभियान का सवाल है, तो एक बार इस नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हो जाए, उसमें सभी पार्टी के लोग रहेंगे, जो भी फैसला होगा, हम उसे कार्यान्वित करेंगे।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, आपने कहा कि 58 प्रतिशत अध्यापकों की नियुक्तियां चाहते हैं, कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर आ गया है, उसकी वजह से यह नहीं हो पा रहा है। यह स्टे किन प्वाइन्ट्स पर है? क्या ऐसे प्वाइन्ट्स पर हैं? जिनका समाधान आप नहीं कर सकते हैं? यदि आप समाधान कर सकते हैं तो कोर्ट का इंतजार क्यों कर रहे हैं?

श्री अर्जुन सिंह: सभापति महोदय, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि कोर्ट ने अलग-अलग स्टेट में स्टे ऑर्डर दिए हैं। सभी स्टे ऑर्डर्स समान रूप से नहीं हैं। आपका जो संकेत है, इसे ध्यान में रखते हुए हम प्रयास करेंगे कि स्टे ऑर्डर्स को वेकेट कराने के लिए हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं, हम इस पर विचार करेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा: सभापति महोदय, भारत के संविधान में विशेष रूप से जो संशोधन हो गया है , जिसमें पांच साल से चौदह वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है, इसके अंतर्गत ही सर्व शिक्षा अभियान की आपकी योजना चालू हुई है। इसमें विशेष रूप से इसलिए कठिनाई आ रही है कि राशि आप दे रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपए आप छोटी-छोटी पुस्तकें खरीदने के लिए दे रहे हैं, टी.वी. के लिए दे रहे हैं, जिनका गांव में कोई उपयोग नहीं है। प्रदेशों में शिक्षकों को एक हजार रुपए महीने पर रख रहे हैं। अगर स्टे भी हुए हैं तो शिक्षक, जिनको गुरुजी कहेंगे व शिक्षाकर्मी कहेंगे, उनको एक हजार रुपए माहवार दे रहे हैं। वे कहते हैं कि जो रेग्युलर पे स्केल है, हमें वह मिलना चाहिए। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनको पूरा स्केल देकर, बाकी की जो और बेकार की बातें इसमें शामिल की हैं, उनको काटकर, पूरा वेतन देने की व्यवस्था करेंगे?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO THE STARRED QUESTIONS

Privatisation of Madarsas and Islamic education

†*163. SHRI ABU ASIM AZMI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Madarsas and Islamic education centres are being privatized; if so, the reasons therefor;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(b) whether Government have any scheme to introduce modern education system therein; if so, the details thereof and if not, the reasons therefor, and

(c) whether Islamic degree holder students get the opportunities for Government services and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (c) Madarsas are run by organizations of the community and there is no proposal to change their existing status.

A comprehensive scheme, namely the Area Intensive and Madarsa Modernization Programme, is already in place. Under its second component, *i.e.* Madarsa Modernization Programme, grants are released to State Governments/U.Ts for further disbursement to NGOs/Voluntary Organizations for teaching subjects such as English, Mathematics, Social Studies and Science along side the traditional curriculum.

Under Graduate and Post Graduate degrees including degrees in Islamic studies, awarded by recognised Universities/Institutions in all subjects, are treated at par for employment purposes.

Payment of statutory dues of loss making PSUs

*164. SHRIMATI S.G. INDIRA: Will the Minister of HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to give a budgetary support of Rs.517 crores to 24 loss making public sector companies to clean the outstanding payment of salary and statutory dues of forty five thousand employees;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that the estimated losses of the above 24 public sector undertakings is now Rs.1800 crores; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) and (b) Yes, Sir. The details are given in the Annex.